

II. समग्र मांग

समग्र मांग* में 2010-11 की ति4 में गिरावट आयी जिसका मुख्य कारण निवेश में नरमी आना था। कंपनी निवेश की मंशा में भी 2010-11 की दूसरी छमाही में कमी आयी। 2011-12 में अब तक निवेश में सुधार होने के कोई चिह्न नहीं दिख रहे। निजी उपभोग मांग में अधोमुखी समायोजन हो रहा होगा किंतु यह अब भी मजबूत बनी हुई है। कंपनी बिक्री वृद्धि 2010-11 की ति4 में मजबूत बनी रही 201-12 की ति1 में भी यह मजबूती बनी रहने की संभावना है। किंतु 2010-11 में लाभ में कमी आ गयी जिसमें बढ़ते ब्याज और कच्चे माल के मूल्यों से मार्जिन दबाव में आ गयी थी। 2010-11 में सरकारी उपभोग व्यय से निजी उपभोग व्यय में मांग का पुनर्संतुलन हुआ। आगे, वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए निवेश में निवेश में कुछ पुनर्संतुलन की आवश्यकता है। 2010-11 में राजकोषीय संकेतकों में सुधार होने के बावजूद सब्सिडी में उच्च वृद्धि से बाजार मूल्य पर जीडीपी में कमी आयी। पेट्रोलियम सब्सिडी कम करने के हाल के उपायों के बावजूद 2011-12 में राजकोषीय गिरावट की संभावना है।

निवेश में नरमी बनी रही

II.1 जीडीपी के व्यय पक्षीय आंकड़े 2010-11 की ति4 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में और मालसूची निर्माण में काफी नरमी दर्शा रहे हैं (सारणी II.1)। जहां इन संख्याओं में संशोधन हो सकता है, वहीं इनसे यह भी पता चलता है कि 2010-11 की दूसरी छमाही में निवेश में नरमी आ गयी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी के अनुसार कंपनी निवेश मंशा पर अद्यतन जानकारी से पता चलता है कि वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं पर हुआ परियोजना व्यय 2010-11 की पहली छमाही में अधिक था किंतु इसकी दूसरी छमाही में इसमें तेज गिरावट आयी। जहां 2010-11 का अनुमानित कंपनी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक था, वहीं 2010-11 की पहली छमाही के स्तर से दूसरी छमाही में 43 प्रतिशत कमी आने से मंदी स्पष्ट दिख रही थी।

II.2 2010-11 की ति3 से आयी यह नरमी चिंता की बात है और निवेश के प्रति सकल मांग में कुछ पुनर्संतुलन को आवश्यक बनाती

सारणी II.1: जीडीपी का व्यय पक्ष (आधार: 2004-05)

(प्रतिशत)

	2009-10 त्व.अ.	2010-11 सं.अ.	2009-10				2010-11			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(वृद्धि दर)										
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	9.1	8.8	6.5	7.6	9.2	12.6	9.4	9.1	9.2	7.7
कुल अन्तिम खपत व्यय	8.7	8.0	9.3	12.2	7.4	6.5	8.6	8.5	7.4	7.5
निजी	7.3	8.6	7.3	8.5	7.0	6.6	8.9	8.9	8.6	8.0
सरकारी	16.4	4.8	21.3	37.5	9.6	6.2	6.7	6.4	1.9	4.9
सकल अचल पूंजी निर्माण	7.3	8.6	-0.4	0.3	8.7	19.2	17.4	11.9	7.8	0.4
स्टॉक में परिवर्तन	90.8	7.4	78.9	86.1	95.4	102.1	11.7	9.0	5.1	4.6
निवल-निर्यात	10.2	-15.3	5.4	-21.1	15.0	70.8	33.8	14.1	-52.6	-34.8
(जीडीपी में हिस्सा)										
कुल अन्तिम खपत व्यय	70.1	69.5	73.1	71.4	73.6	63.2	72.6	71.0	72.3	63.1
निजी	58.5	58.3	61.8	60.2	60.5	52.4	61.6	60.1	60.1	52.6
सरकारी	11.6	11.2	11.3	11.2	13.1	10.8	11.0	10.9	12.2	10.5
सकल अचल पूंजी निर्माण	32.0	32.0	30.4	31.9	30.9	34.5	32.6	32.7	30.5	32.1
स्टॉक में परिवर्तन	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.3	3.4
निवल-निर्यात	-7.2	-5.6	-6.3	-7.3	-8.8	-6.5	-7.7	-7.6	-3.8	-3.9

ज्ञापन:

(₹ करोड़)

बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	48,69,317	52,98,129	11,12,318	11,37,985	12,55,040	13,63,974	12,17,270	12,41,332	13,70,188	14,69,339
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

त्व.अ.: त्वरित अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।

नोट: चूंकि प्रमुख मंदां ही सारणी में शामिल की गई है, इसलिए आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

* सुपरिचित सीमाओं के बावजूद व्यय पक्षीय सकल देशी उत्पाद के आंकड़े समग्र मांग के घटकों के लिए प्रतिनिधि के रूप में उपयोग में लाये जा रहे हैं।

है। 2010-11 में 796 परियोजनाओं को 4,60,000 करोड़ रुपये के योजनाबद्ध परियोजना व्यय के लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी जबकि 2009-10 में 754 परियोजनाओं को 4,56,000 करोड़ रुपये के योजनाबद्ध परियोजना व्यय के लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी। कंपनी निवेश में बिजली क्षेत्र आगे है जिसके बाद धातु तथा धातु उत्पाद और दूरसंचार का स्थान है और अब तक इनका आधार व्यापक नहीं हुआ है। जहां मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए आवश्यक हो गयी ब्याज वृद्धि से निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, वहीं बेहतर कार्यान्वयन से निवेश में सुधार हो सकता है। सरकार ने निवेश की बाधाओं को हटाने और मल्टि-ब्रांड खुदरा क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों में एफडीआइ को प्रोत्साहन देने की अपनी मंशा घोषित कर दी है।

निजी उपभोग मांग में कमी आने के बावजूद उसकी मजबूती बरकरार है

II.3 व्यय पक्ष से वृद्धि के प्रेरकों से पता चलता है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) की प्रमुखता बनी हुई थी। निजी उपभोग में उछाल मुख्यतः कृषि वृद्धि में सुधार से प्रेरित

था और इसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु घटक की सहायता प्राप्त थी (सारणी II.1)।

कंपनी बिक्री की वृद्धि मजबूत बनी रही किंतु लाभ में कमी आयी

II.4 निजी उपभोग मांग में मजबूती दर्शाते हुए गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री 2010-11 में लगभग 20 प्रतिशत और वर्ष की चौथी तिमाही में भी बढ़ी (सारणी II.2)। इसके अलावा, बेहतर मांग की अपेक्षा में कंपनियों ने स्टॉक जमा किया जिससे बिक्री-व्यापारगत माल अनुपात बढ़ गया (चार्ट II.1)। किंतु 2010-11 में परिचालन लाभ और निवल लाभ में कमी आ गयी जिसका कारण निविष्टि और ब्याज लागत का अधिक होना था। लाभ मार्जिन घटने और ब्याज बहिर्वाह बढ़ने से ब्याज कवरेज अनुपात भी, जो कि यह दर्शाता है कि सकल लाभ ब्याज भुगतान को कितनी बार कवर करता है, पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो गया। 2011-12 की ति1 के लिए अर्जन का अनुमान मजबूत उच्च स्तरीय वृद्धि दर्शाता है जिससे मांग की स्थिति अच्छी बनी रहने का संकेत मिलता है। किंतु मार्जिन का संकुचन लाभ को कुछ कम कर सकता है। प्रारंभिक परिणाम इन आशंकाओं की पुष्टि करते हैं (सारणी II.3)।

सारणी II.2: कारपोरेट क्षेत्र - वित्तीय निष्पादन

(प्रतिशत)

	2009-10	2010-11 (अ)	2009-10				2010-11			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कंपनियों की संख्या										
			2196							
वृद्धि दर प्रतिशत में										
बिक्री	12.8	19.7	-0.8	0.6	23.0	29.8	25.3	19.2	17.1	19.9
अन्य आय*	15.5	3.8	51.5	3.4	7.8	8.3	-23.0	56.2	8.4	-24.7
व्यय, जिसमें से:	10.6	22.3	-4.8	-2.3	20.6	30.9	29.8	20.5	19.1	22.4
कच्चा माल	13.2	25.7	-13.8	-4.2	33.5	43.7	37.7	21.5	19.7	26.6
स्टाफ लागत	8.5	18.4	8.4	6.3	5.3	14.0	16.3	20.0	20.5	20.0
परिचालन लाभ (पीबीडीआइटी)	27.8	11.5	6.7	14.4	59.3	39.4	15.4	7.8	10.5	14.6
मूल्यहास	22.0	15.3	22.4	21.2	23.2	21.2	20.2	16.7	13.1	13.3
ब्याज	-3.8	20.0	5.5	-0.2	-13.6	-3.9	29.9	5.7	21.9	29.5
सकल लाभ (पीएटी)	32.4	7.5	7.6	12.9	91.0	43.4	1.6	9.2	9.1	11.9
अनुपात प्रतिशत में										
बिक्री के प्रति स्टॉक में परिवर्तन#	1.0	1.7	0.4	1.6	0.7	0.6	2.2	0.8	1.2	1.7
बिक्री के प्रति (पीबीडीआइटी)	16.8	15.7	17.5	17.3	16.8	15.9	16.2	15.6	15.9	15.1
बिक्री के प्रति कर पश्चात लाभ	9.4	8.5	10.4	9.5	9.0	9.1	8.5	8.6	8.3	8.4
बिक्री के प्रति ब्याज	2.6	2.6	2.7	2.9	2.6	2.3	2.9	2.6	2.7	2.5
सकल लाभ के प्रति ब्याज	17.6	19.6	17.2	19.8	17.6	16.1	21.1	19.1	19.7	19.1
ब्याज कवरेज (टाईम)	5.7	5.1	5.8	5.1	5.7	6.2	4.8	5.2	5.1	5.2

* : असाधारण आय/व्यय यदि स्पष्टतः सूचित किया गया हो तो वह अन्य आय में शामिल नहीं है।

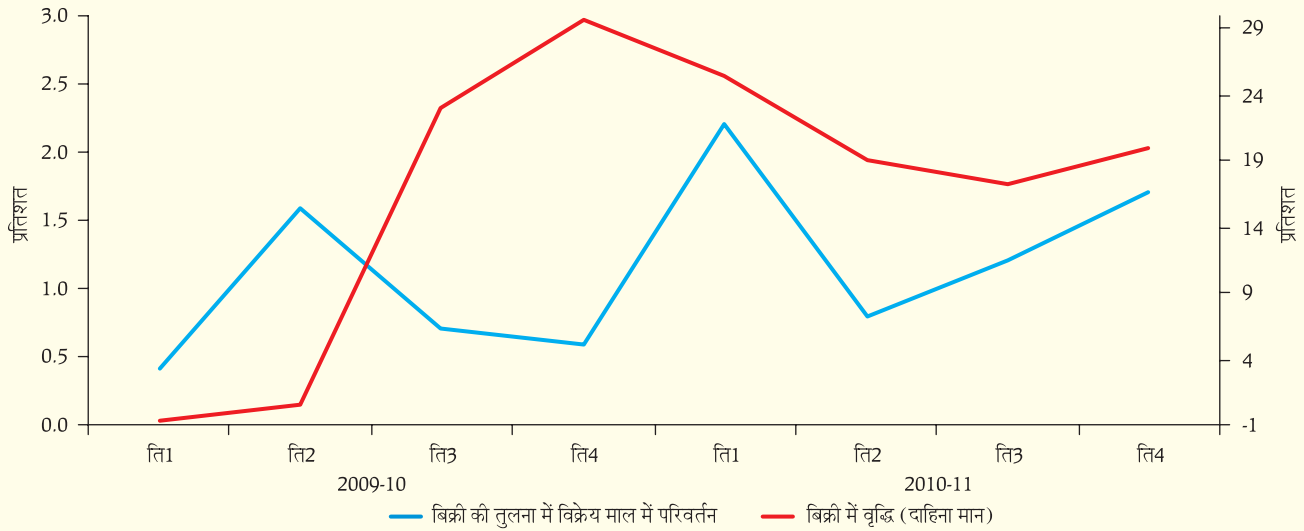
: इस मद को स्पष्टतः सूचित करनेवाली कंपनियों के लिए।

पीबीडीआइटी: मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ।

पीएटी: कर पश्चात लाभ।

टिप्पणी : वृद्धि दरें कंपनियों के सामान्य सेट के लिए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में संदर्भाधीन अवधि की तुलना में स्तर में प्रतिशत परिवर्तन है।

चाट II.1: बिक्री में वृद्धि - विक्रेय माल अनुपात



बाह्य मांग में सुधार हुआ किंतु अनिश्चय बना हुआ है

II.5 2010-11 की ति4 में निवल बाह्य मांग में कुछ सुधार हुआ है। आयात की तुलना में निर्यात की गति अधिक रहने से जीडीपी में निवल निर्यात के नकारात्मक योगदान की मात्रा में कमी आयी। आगे, पुन; उबरी वैश्विक वृद्धि की चिंता के कारण बाह्य मांग के संबंध में कुछ

अनिश्चितता है किंतु विशेष रूप से भारत में बाह्य मांग समग्र मांग में कम योगदान देती है।

घाटे के संकेतकों में सुधार से वृद्धि के पुनर्संतुलन की अच्छी आशा है

II.6 केंद्र सरकार के 2010-11 के अंतिम लेखे संशोधित अनुमान से काफी बेहतर रहे। घाटे के मुख्य संकेतकों ने संशोधित अनुमान की तुलना में सुधार दर्शाया जिससे कर और करेतर राजस्व की उच्च वसूली और राजस्व तथा पूंजी घटक का योजना व्यय कम रहने का पता चलता है। प्राथमिक संकेतक दर्शाते हैं कि केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2010-11 में कम होकर जीडीपी के 7.7 प्रतिशत रह गया (सारणी II.4 और II.5)। संयुक्त राजस्व घाटे में भी काफी कमी आयी। केंद्र ने 2010-11 में अपेक्षा से अधिक हुई राजस्व प्राप्ति का उपयोग प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्रों (ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने, राज्यों को योजना सहायता और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूँजीकरण) के बढ़े हुए परिव्यय के वित्तपोषण के लिए किया।

सारणी II.3: 2011-12 की ति 1 के प्रारंभिक परिणाम

	2010-11		2011-12
	ति1	ति4	ति1
1	2	3	4
कंपनियों की संख्या	127		
प्रतिशत वृद्धि दर			
बिक्री	27.3	26.1	27.1
अन्य आय*	-15.1	17.3	85.4
व्यय, जिसमें से	35.8	29.6	25.0
कच्चा माल	50.9	34.9	29.8
स्टाफ लागत	15.4	25.8	26.3
परिचालन लाभ (पीबीडीआयटी)	16.2	23.5	24.4
मूल्यहास	5.1	26.1	27.4
ब्याज	26.8	26.6	14.6
सकल लाभ (पीएटी)	12.4	33.8	29.2
प्रतिशत अनुपात			
बिक्री के प्रति स्टॉक में परिवर्तन#	4.6	1.5	2.2
बिक्री के प्रति (पीबीडीआयटी)	18.7	19.3	18.3
बिक्री के प्रति कर पश्चात लाभ	13.1	15.1	13.3
बिक्री के प्रति ब्याज	1.3	1.2	1.2
सकल लाभ के प्रति ब्याज	7.4	6.1	6.6
ब्याज कवरेज (टाईम)	13.5	16.3	15.1

: इस मद को स्पष्टतः सूचित करनेवाली कंपनियों के लिए।

* : असाधारण आय/व्यय यदि स्पष्टतः सूचित किया गया हो तो वह अन्य आय में शामिल नहीं है।

टिप्पणी: अंतिम आंकड़े।

सब्सिडी बजट अनुमान से अधिक हो सकती है

II.7 2010-11 में सुधार के बावजूद 2011-12 में राजकोषीय गिरावट की संभावना बनी हुई है। 2011-12 के लिए व्यय से प्रेरित राजकोषीय सुधार के सरकार के बजट रुझान को राजकोषीय सुदृढीकरण तथा स्फोटिकारी आशंकाओं को रोकने की दिशा में पहल के रूप में देखा गया। किंतु 2011-12 के लिए अनुमानित कम सकल राजकोषीय

सारणी II.4: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयता
1	2	3	4	5
केंद्र				
2009-10	3.1	5.2	6.4	53.7
2010-11 सं.अ.	2.0	3.4	5.1	49.9
	(1.7)	(3.1)	(4.7)	
2011-12 ब.अ.	1.6	3.4	4.6	48.5
राज्य*				
2009-10	1.1	0.5	2.8	22.7
2010-11 सं.अ.	0.9	0.3	2.5	21.0
2011-12 ब.अ.	0.6	-0.2	2.1	20.6
संयुक्त				
2009-10	4.5	5.7	9.2	68.9
2010-11 सं.अ.	3.2	3.7	7.7	64.0
2011-12 ब.अ.	2.4	3.3	6.8	62.7

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान

* : राज्यों के आंकड़े 24 राज्य सरकारों के हैं जिनमें से चार लेखा अनुदान हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े महालेखापाल द्वारा 31 मई 2011 को जारी अर्न्तम लेखों से हैं।

स्रोत: बजट अनुमान केंद्र और राज्य सरकार के हैं।

घाटा (जीएफडी)-जीडीपी अनुपात वृद्धि में कमी आने के कारण सब्सिडी में व्यापक ऊर्ध्वमुखी जोखिम और राजस्व में अधोमुखी जोखिम के कारण चुनौतीपूर्ण बन गया है।

II.8 2011-12 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी 2010-11 के संशोधित अनुमान से कम रहने का अनुमान होने के बावजूद 2011-12 में पेट्रोलियम सब्सिडी का वास्तविक स्तर अनुमानित स्तर से बढ़ जाने की अपेक्षा है। जून 2011 में डीजेल, पीडीएस केरोसिन और देशी एलपीजी के देशी मूल्यों में आंशिक ऊर्ध्वमुखी संशोधन के बाद भी वसूली में कमी लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये रहने की संभावना के कारण पेट्रोलियम सब्सिडी में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, 2010-11 की चौथी तिमाही के लिए तेल की मार्केटिंग कंपनियों की वसूली में कमी के मुआवजे के लिए किया गया भुगतान भी चालू राजकोषीय वर्ष के सब्सिडी भार में जीडीपी

के 0.2 प्रतिशत का भार बढ़ायेगा। पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क समाप्त/कम करने से भी केंद्र को जीडीपी के लगभग 0.3 प्रतिशत की हानि होगी जिससे केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा। केंद्र के लिए तेल क्षेत्र से कुल राजकोषीय गिरावट जीडीपी के लगभग 1 प्रतिशत हो सकती है। इसके अलावा, उर्वरक सब्सिडी में भी वृद्धि हो सकती है। अतः राजस्व लेखे में दीर्घकालिक सुधार के लिए यह आवश्यक है कि कर वसूली संकट-पूर्व स्तर पर लायी जाए और साथ ही डीजेल, केरोसिन तथा एलपीजी के नियंत्रित मूल्यों को चरणबद्ध रूप से शीघ्र समाप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

II.9 अप्रैल-मई 2011 के दौरान केंद्र सरकार का राजस्व घाटा और जीएफडी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक था जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आना था। 2011-12 की पहली तिमाही

सारणी II.5: संयुक्त वित्त

मद	वृद्धि दर (प्रतिशत)			जीडीपी का प्रतिशत		
	2009-10	2010-11 (सं अ)	2011-12 (ब अ)	2009-10	2010-11 (सं अ)	2011-12 (ब अ)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल व्यय	15.8	21.7	6.5	28.0	28.4	26.5
2. राजस्व व्यय	16.4	20.0	6.4	23.9	23.9	22.3
3. पूंजी व्यय	12.2	32.2	7.3	4.1	4.5	4.2
4. विकासेतर व्यय	20.7	14.3	9.9	11.7	11.1	10.7
5. विकास	12.5	26.9	4.1	16.0	16.9	15.4
6. राजस्व प्राप्तियां	8.4	32.6	7.7	18.3	20.1	19.0
i) कर राजस्व (निवल)	6.3	25.6	17.1	15.0	15.6	16.1
ii) करेतर राजस्व	18.8	63.9	-25.0	3.3	4.5	3.0

की मुख्य सूचना दर्शाती है कि सकल प्रत्यक्ष कर वसूली बढ़ने के बावजूद कंपनी कर की धन वापसी की बड़ी राशि के कारण अप्रैल-जून 2010 की तुलना में निवल कर वसूली में गिरावट आयी।

राज्य वित्त की स्थिति ठीक लगती है

II.10 राज्य सरकारें भी 2008-10 के दौरान की विफलता के बाद 2010-11 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया की ओर लौट गयी। अब तक प्राप्त 24 राज्य सरकारों के 2011-12 के बजटों पर आधारित 2010-11 के संशोधित अनुमान इस बात की पुष्टि करते हैं कि समेकित स्तर पर 2010-11 में राज्य मुख्य घाटा अनुपात में अनुमानित गिरावट प्राप्त कर सकते हैं। यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता में वृद्धि दर्शाती है।

II.11 एक असमेकित विश्लेषण दर्शाता है कि 2011-12 में राज्यों के राजस्व खाते में अनुमानित व्यय का मुख्य कारण राजस्व व्यय में गिरावट था जबकि राजस्व प्राप्ति-जीडीपी अनुपात 11.7 प्रतिशत पर स्थिर रहने की अपेक्षा है। किंतु राजस्व व्यय वृद्धि में नरमी से विकास व्यय (सामाजिक और आर्थिक सेवा) की वृद्धि में तेज गिरावट होकर यह 2010-11 (संअ) के 26.0 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 9.0 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। राजस्व खाते में सुधार के अनुरूप राज्यों का जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2011-12 में कम रहने का अनुमान है। किंतु जीडीपी-पूँजी व्यय अनुपात का 2011-12 में 2.1 में का अनुमान है और यह 2006-09 में प्राप्त

उच्च स्तर पर नहीं आ पाया है। अनेक राज्य पेट्रोलियम उत्पादों पर उनके राज्य प्रशुल्क कम कर रहे हैं जिससे राज्य वित्त पर प्रभाव पड़ सकता है।

II.12 समग्र रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य अपने वित्त को मध्यावधि संदर्भ में मजबूत पथ पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की वर्तमान गति तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए पथ के समरूप है। इस प्रकार, राज्यों की राजकोषीय स्थिति प्रोत्साहनजनक लग रही है किंतु चुनौती यह है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की यह मंशा परिणाम में परिणत की जाए और यह कार्य करते समय राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया के साथ समझौता न किया जाए।

2011-12 में मांग में कमी आने की संभावना है

II.13 निवेश और उपभोग में और कमी आने की संभावना है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति से वास्तविक उपभोग में कमी आयी है और मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई प्रणाली में अल्पावधि संदर्भ में मांग को रोकने का कार्य करेगी। उपभोग में मंदी को अब तक ब्याज दर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों तक नियंत्रित किया गया है जैसे कि कारों की बिक्री प्रभावित हुई है। निवेश की ओर मांग में कुछ पुनर्संतुलन सहायक सिद्ध होगा और औद्योगिक नीतिगत कार्रवाई और कार्यान्वयन इस पुनर्संतुलन में सहायक हो सकते हैं। सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता समग्र मांग के पुनर्संतुलन में सहायक हो सकती है।